दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Module – 4)

निर्धारित समय: तीन घंटे Time allowed: Three Hours	DTVF/19 (N-M)–M–**GS14**	अधिकतम अंक: 250 Maximum Marks: 250

Name: Devendra Prakash Meena **Mobile Number:** ____________

Medium (English/Hindi): Hindi **Reg. Number:** * 7102

Center & Date: Delhi, 15/07/19 **UPSC Roll No. *(If allotted)*:** 1134510

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*इसमें **बीस** प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

1. भारत में सहकारी संघवाद के संबंध में कौन-से संवैधानिक प्रावधान हैं? साथ ही प्रतिस्पर्द्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिये नीति आयोग द्वारा हाल ही में किये गए कुछ उपायों पर भी चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

What are the Constitutional provisions regarding cooperative federalism in India? Also discuss some of the recent measures taken by NITI Aayog to foster competitive federalism. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान में ~~भार~~ संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है अर्थात् केन्द्र तथा राज्य के स्तर पर भिन्न-भिन्न शासन व्यवस्था विद्यमान है।

सहकारी संघवाद से तात्पर्य केन्द्र तथा राज्य एवं विभिन्न राज्यों में आपसी सद्भावना के सिद्धांत से है।

सहकारी संघवाद के संवैधानिक प्रावधान

→ अनुसूची 7 :- इसके द्वारा राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है ताकि किसी तरह का मतभेद न हो।

→ अनुच्छेद - 280 :- इसके अन्तर्गत ~~के~~ वित्त आयोग के गठन का निर्देश दिया गया है, जो केन्द्र तथा राज्यों के मध्य करों के अन्तरण का कार्य करता है।

→ GST काउन्सिल :- इसके अन्तर्गत राज्यों को प्रभावी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

→ अन्तर-राज्यीय परिषद :- अनुच्छेद - 263 के तहत विवादों के समाधान के लिए इसके गठन का प्रावधान है।

प्रतिस्पर्धी संघवाद

इस प्रकार के संघवाद में विभिन्न राज्य आपस में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा द्वारा श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करने की कोशिश करते है।

नीति आयोग द्वारा किये गये उपाय

→ नीति आयोग ने विभिन्न राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए इंडेक्स जारी किये गये है। जैसे -

→ स्वास्थ्य इंडेक्स

→ कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स

→ पिछड़े राज्यों को प्रतिस्पर्धा में बेहतर ~~स्थिति~~ प्रदर्शन करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

→ नार्थ ईस्ट को प्रतिस्पर्धा में बनाये रखने के लिए नीति फोरम फॉर नार्थ ईस्ट का गठन।

निष्कर्ष – सारांशतः स्पष्ट है कि भारतीय सहकारी संघवाद अब प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद में बदल चुका है, जो सशक्त राज्य, समृद्धशाली केन्द्र की अवधारणा को पुष्ट करता है

Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

2. सोशल मीडिया के युग में आदर्श आचार संहिता (एम.सी.सी.) का प्रवर्तन चुनौतीपूर्ण हो गया है। स्पष्ट कीजिये। इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किये गए कुछ उपायों का भी उल्लेख कीजिये। (150 शब्द) 10

Enforcement of Model Code of Conduct (MCC) has become challenging in the era of social media. Elucidate. Also mention some of the measures taken by the Election Commission of India in this regard. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

आचार संहिता से तात्पर्य चुनाव से पूर्व निश्चित राजनीतिक द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले उन-नियमों का समुच्चय है, जो निर्वाचन व्यवस्था को विकृति से बचाता है।

सोशल मीडिया युग में इसका प्रवर्तन चुनौतीपूर्ण हो गया है, जिसके निम्नलिखित कारण है -

→ सोशल मीडिया पर किसी भी सूचना के स्रोत का पता लगाना बहुत कठिन है। अत: दोषी पर कार्यवाही नहीं हो पाती।

→ भारत में लगभग 566 मिलियन इंटरनेट उपयोक्ता है किन्तु डिजिटल लिटरेसी केवल 15% है, ऐसे में निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना कठिन है।

→ सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तथा कोई भी ग्रुप बनाकर प्रचार कर सकता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

→ सोशल मीडिया पोस्ट ट्रुथ के सिद्धांत के द्वारा मतदाता की अभिवृत्ति में परिवर्तन का बड़ा कारण बन रहा है।

निर्वाचन आयोग के द्वारा किये गये उपाय

आचार संहिता के प्रवर्तन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ कदम उठाये है -

→ सोशल मीडिया पर किये भी प्रचार सामग्री को किसके द्वारा प्रमोट किया गया, इसकी जानकारी पोस्ट के साथ दी जानी चाहिए।

→ निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी परिस्थिति में आचार संहिता के उल्लंघन के संदर्भ में शिकायत के लिए ई-विजिल नामक मोबाइल एप्लीकेशन निर्मित की।

आगे की राह

– आदर्श आचार संहिता निष्पक्ष निर्वाचन का मूल है। अतः इसके प्रभावी क्रियान्वयन का प्रयास किया जाना चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

3. किन परिस्थितियों में एक विधायक को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है? क्या आप सहमत हैं कि इसके लाभप्रद परिणाम के अपेक्षाकृत दुष्प्रभाव अधिक हैं? (150 शब्द) 10

What are the circumstances under which a legislator can be disqualified under anti-defection law? Do you agree that it has caused more harm than good? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

52 वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। जिसमें दलबदल को परिभाषित किया गया।

अयोग्यता

→ यदि कोई विधायक/ सांसद स्वेच्छा से दल की सदस्यता का त्याग कर दे।

→ यदि कोई मनोनीत सांसद/विधायक 6 माह पश्चात, किसी दल में सम्मिलित हो जाये।

→ कोई निर्दलीय उम्मीदवार किसी दल में शामिल हो जाये।

→ 2/3 से कम संख्या में दल में विलय करने पर

अपवाद

→ 2/3 से अधिक संख्या में किसी दल में विलय

→ अध्यक्ष, उपसभापति द्वारा अपनी दलीय सदस्यता का त्याग

दलबदल कानून के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में 'आया राम गया राम' की मानसिकता

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

दूर कर स्थायित्व एवं दलीय अनुशासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया किन्तु इसके दुष्प्रभाव सामने आये है -

→ किसी विधायक / सांसद द्वारा दल के विरुद्ध भाषण देने को व्हिप का उल्लंघन माना जाता है, जो बाध्य स्वीकृति तथा असहमति के खात्मे के समान है।

→ इससे स्थायित्व की बजाय हॉर्स ट्रेडिंग की समस्या बढ़ी है। जैसे- कर्नाटक, गोवा में हाल में सरकारों का गिरना।

→ अध्यक्ष द्वारा निर्णय दिया जाना पूर्वाग्रह से मुक्त होता है।

→ असहमति दर्ज नहीं करा पाने की स्थिति में गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है।

आगे की राह

→ दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश देते हुए कहा कि
- केवल विश्वास, अविश्वास प्रस्ताव पर दल बदल लागू हो।
- किसी तटस्थ द्वारा निर्णय हो।

→ दलबदल एक महत्त्वपूर्ण कानून होने के बावजूद बेहतर क्रिया-वयन का अभाव है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

4. राष्ट्रपति और राज्यपालों के अध्यादेश लागू करने की शक्तियों से संबंधित विभिन्न मुद्दे क्या हैं? साथ ही अध्यादेश लागू करने की शक्ति के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु संरक्षोपायों का उल्लेख कीजिये। (150 शब्द) 10

What are the various issues around ordinance making power of President and Governors? Also discuss the safeguards which are in place to prevent misuse of ordinance making power. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 एवं 213 में क्रमश: राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है

महत्व

→ जब दोनो सदन एक साथ संचालन में न हो। तब कानून निर्माण।
→ त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता होने पर।

मुद्दे

→ यह शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन है।

→ विधि निर्माण में संसद की भागीदारी को हटाने के समान है।

→ बिना आवश्यक चर्चा के कानून निर्माण गुणवत्ता पूर्ण नहीं होता।

→ कई बार अध्यादेश को बार-बार जारी कर संवैधानिक भावना का उल्लंघन किया गया। जैसे बिहार में कृष्णाकुमार सिंह वाद में SC ने बार-बार जारी करने को असंवैधानिक कहा गया।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

→ कई बार त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होने पर भी अध्यादेश जारी किया गया।
ex- हाल ही में राजस्थान में।

रोकने के उपाय

→ संविधान में उल्लेखित है कि संसद के सत्र के संचालन के पश्चात् 6 हफ्ते में इसका पारित होना आवश्यक है, अन्यथा यह निरसित हो जाएगा।

→ संविधान संशोधन, अध्यादेश के द्वारा नहीं किया जा सकता।

→ सुप्रीम कोर्ट ने भी अनेक निर्णयों - डी.सी. वाधवा वाद, कृष्णा कुमार वाद आदि में अध्यादेश के दुरुपयोग को असंवैधानिक कहा है।

आगे की राह

अध्यादेश राष्ट्रपति को दी गई वह शक्ति है, जो कानून निर्माण की निरन्तरता बनाये रखती है। अतः आवश्यक है कि इसका प्रयोग केवल अनिवार्यता की स्थिति में ही किया जाये।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

5. लोकपाल के कर्त्तव्य और शक्तियाँ क्या हैं? क्या लोकपाल का पद सरकार और अन्य, जिनकी जाँच हेतु इसे आज्ञापित किया गया है, से स्वतंत्र है? (150 शब्द) 10

What are the duties and powers of Lokpal? Is the office of the Lokpal independent of the government and others whom it is mandated to scrutinise? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

प्रशासन में बढ़ते भ्रष्टाचार को कम करने तथा जाँच प्रणाली को मजबूत करने के लिए लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 द्वारा लोकपाल की नियुक्ति की गई।

कर्त्तव्य एवं शक्तियाँ

→ प्रशासन में निहित भ्रष्टाचार की जाँच करना एवं त्वरित कार्यवाही करना।

→ निर्णयों के संदर्भ में पक्षपात रहित होना।

→ संसाधनों के अनुकूलतम दोहन को सुनिश्चित करना।

लोकपाल की स्वतंत्रता

→ नियुक्ति प्रक्रिया में इसका चयन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य निम्न हैं।

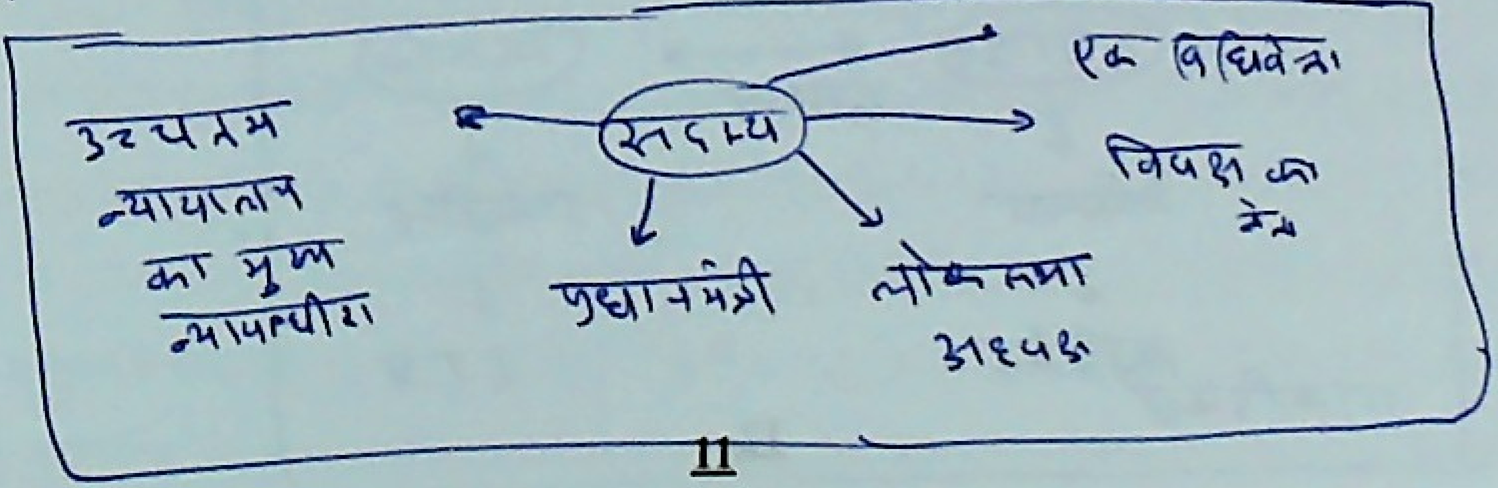

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

→ हटाने का अधिकार एक समिति को दिया गया है।

→ वेतन- भत्ते संचित निधि पर भारित है।

अतः स्पष्ट है कि किसी भी दबाव से बचने के सभी रक्षोपाय किये गये है।

अतः लोकपाल का पद एक वस्तुनिष्ठ निर्णय देने मे सक्षम है।

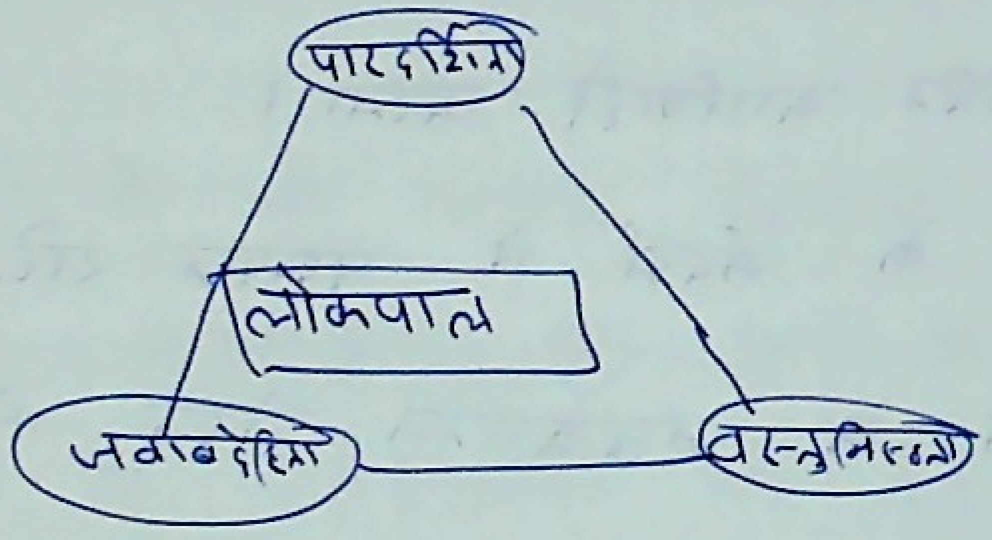

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

6. भारत में सुशासन के मार्ग में आने वाली कुछ प्रमुख बाधाओं को गिनाइये। इन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए सुशासन के लिये आवश्यक पूर्व-शर्तों की विवेचना कीजिये। (150 शब्द) 10

Enumerate some of the key barriers to good governance in India. Taking cues from these barriers, discuss the necessary pre-conditions for good governance. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सुशासन से तात्पर्य शासन का वह रूप जो ~~राष्ट्र~~ राष्ट्र के संसाधनों का अनुकूलतम दोहन करते हुये ऐसा वातावरण उपलब्ध कराये जो व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुरूप विकास का अवसर प्रदान करे।

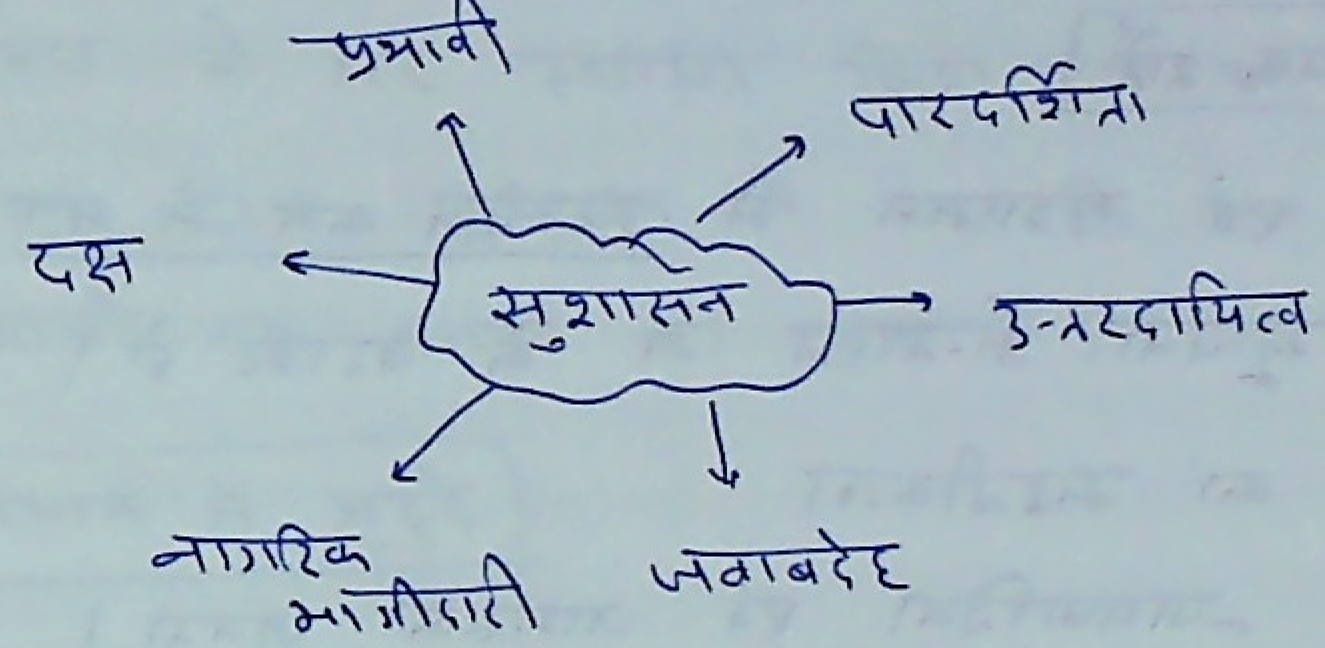

मार्ग में बाधायें

→ सिविल सेवकों की आभिजात्य ~~एवं~~ मनोवृत्ति एवं यथास्थितिवादिता

→ जनता एवं प्रशासन में सूचना अन्तराल

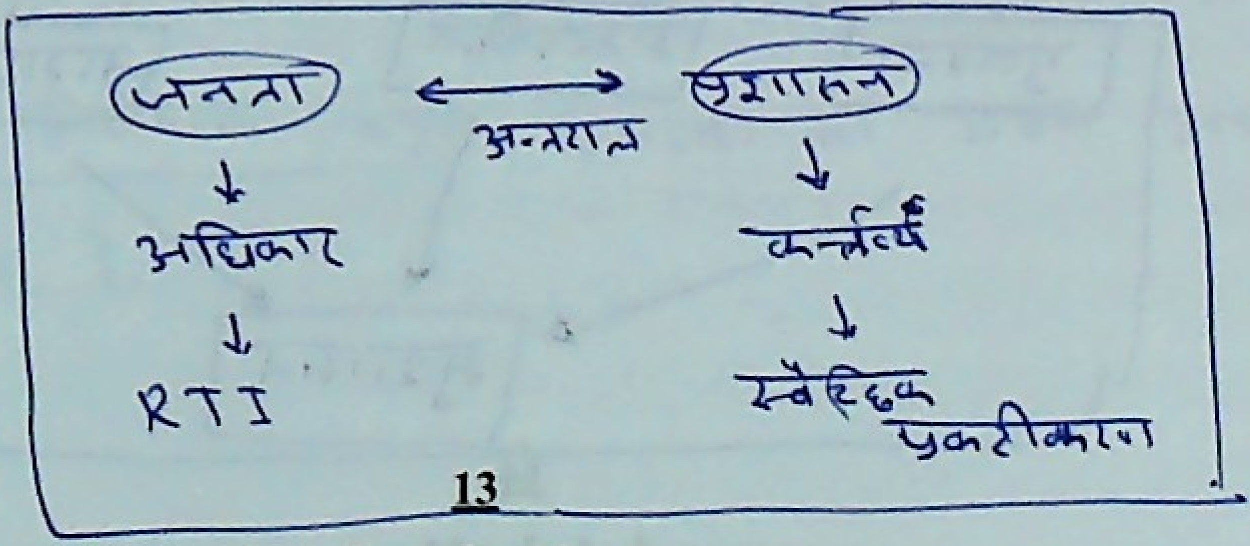

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

→ नियमों का उल्लंघन एवं जटिलता।

→ जनता में जागरूकता एवं शिक्षा का अभाव।

→ न्यायपालिका में लंबित मामले।

→ राजनीति का अपराधीकरण। (ADR की रिपोर्ट के अनुसार लगातार बढ़ा है

वर्ष	2009	2014	2019
आपराधिक प्रवृत्ति	27%	34%	43%

आवश्यक शर्तें

→ जनता एवं प्रशासन में इंटरफेस कम से कम हो तथा सूचना अन्तराल न के बराबर हो।

→ नियमों का सरलीकरण

→ सक्रिय न्यायपालिका एवं जागरूक जनता।

→ सिविल सेवकों में बुनियादी मूल्यों का विकास।

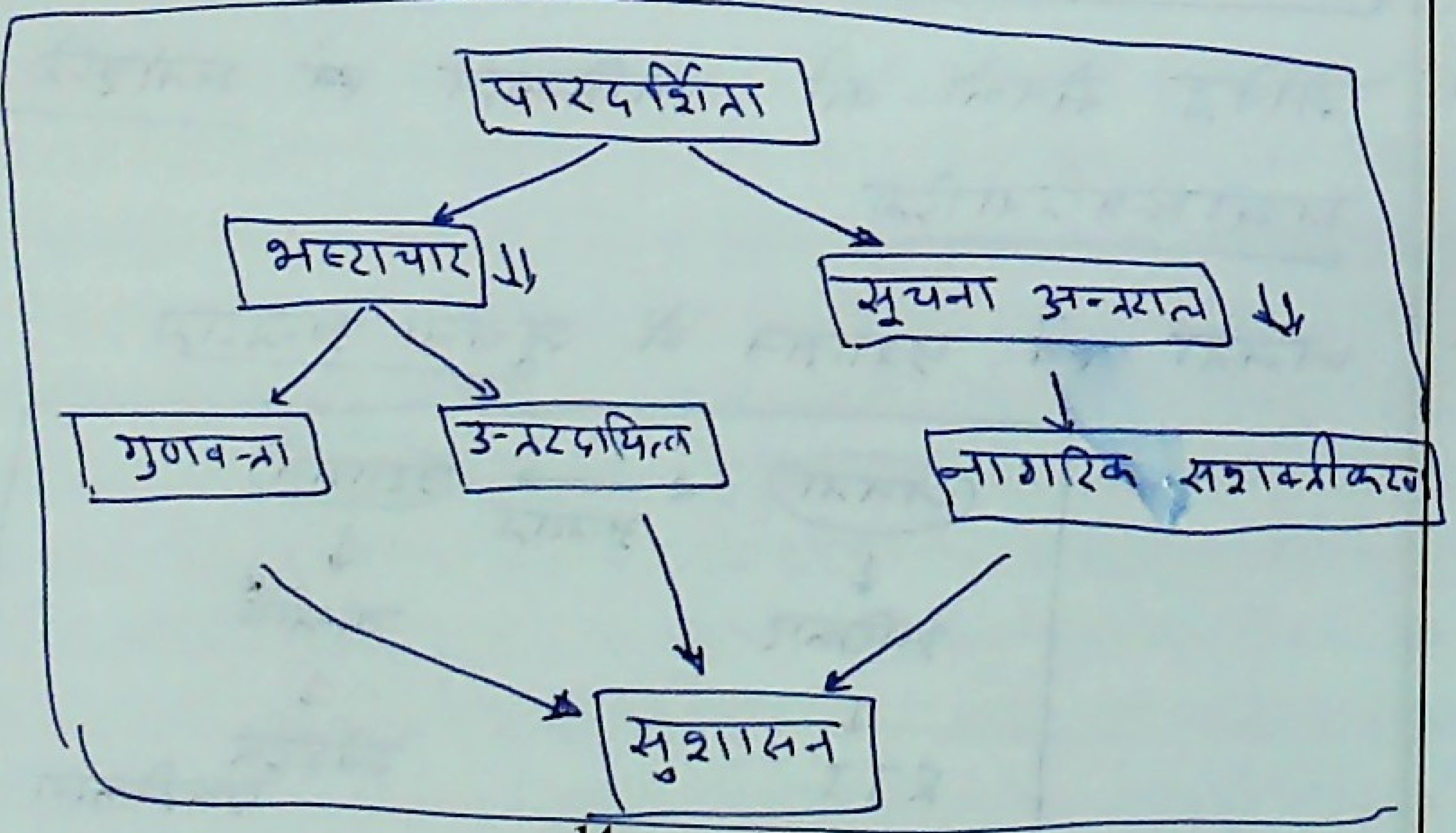

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

7. अनुच्छेद 370 की संवैधानिक स्थिति क्या है? वर्तमान परिदृश्य में इससे संबंधित मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

What is the Constitutional status of Article 370? Discuss issues and challenges related to it in the current scenario. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान द्वारा जम्मू- कश्मीर की विशेष स्थिति को देखते हुये कुछ विशिष्ट प्रावधान प्रदान किये गये, जिनका संबंध अनुच्छेद 370 से है।

संवैधानिक स्थिति - संविधान में इसे अस्थायी उपबंध की तरह स्थापित किया गया था किन्तु J & K उच्च न्यायालय ने कहा कि अब यह स्थायी रूप धारण कर चुका है।

वर्तमान में मुद्दे

→ कुछ लोगो का मानना है कि J & K के पिछड़ेपन का कारण यह अनुच्छेद है।

→ अनुच्छेद 370 के तहत केन्द्र द्वारा लागू कानून वहाँ लागू नहीं होते, जो राज्य को कई प्रकार से नुकसान दायक है। जैसे - जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) का गठन अभी किया गया है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

→ अनुच्छेद- 370 के कारण J&K का शेष भारत से जुड़ाव नहीं हो पाया है।

→ अनुच्छेद- 370 के कारण ही अलगाववादी J&K में प्रभावी है।

चुनौतियाँ

- चूंकि अनुच्छेद 370 वर्तमान में भले ही अस्थायी हो किन्तु जब तक राज्य विधानमंडल द्वारा संविधान सभा का गठन नहीं किया जाता, इसे हटाना मुश्किल है।

- अनुच्छेद 370 के बारे में भ्रामक प्रचार द्वारा राजनीतिक दल जनता को गुमराह करते है।

- अनुच्छेद -370 ही वह सेतु है जो इसे शेष भारत से जोड़ता है।

आगे की राह

- वर्तमान परिस्थितियों में जहाँ तनाव की स्थिति है, इसे नहीं हटाया जाना चाहिए क्योंकि इससे आमजन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

- सरकार को सामाजिक- आर्थिक विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

8. आपके अनुसार भारत में लोक सेवाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख विकार कौन-से हैं? क्या लोक सेवाओं में पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री) इनमें से कुछ विकारों का समाधान कर सकता है? (150 शब्द) 10

What do you think are some of the major ailments afflicting civil services in India? Can lateral entry in civil services address some of these ailments? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

लोक सेवाओं को भारतीय लोकतंत्र का इस्पाती ढाँचा कहा जाता है, क्योंकि प्रशासन को जनता तक पहुँचाना इन्ही की जिम्मेदारी है।

लोक सेवाओं को प्रभावित करने वाले विकार

अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद कुछ विकार उपस्थित है -

→ सिविल सेवकों की अभिजात्यता एवं स्वयं को स्वामी समझने की मानसिकता।

→ सिविल सेवकों में अपारदर्शिता का आग्रह

→ प्रशासनिक भ्रष्टाचार एवं इसका सामाजिक स्वीकारण।

→ राजनीति - नौकरशाही गठबंधन।

→ कमजोर तबके के प्रति संवेदनशीलता का अभाव।

→ पदानुक्रम के कारण उत्पन्न लालफीताशाही

→ यथास्थितिवादिता एवं विशेषज्ञता का अभाव।

सिविल सेवाओं में इन विकारों को दूर करने के लिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

होता समिति आदि ने लेटरल एंट्री की सिफारिश की है।

विकारों की समाप्ति में योगदान:

→ इससे प्रशासन में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तथा विशेषज्ञता आयेगी।

→ यथास्थितिवादिता की समस्या दूर होगी।

→ निजी क्षेत्र की बेहतर वर्कप्लेस कल्चर द्वारा लालफीताशाही को कम किया जा सकता है।

→ लेटरल एंट्री द्वारा संसाधनों का अनुकूलतम दोहन संभव हो सकेगा।

चुनौतियां

→ लेटरल एंट्री द्वारा उत्तरदायित्व में कमी की संभावना क्योंकि इनका कार्यकाल 3-5 वर्ष।

→ बुनियादी मूल्यों का अभाव हो सकता है।

→ करियर ब्यूरोक्रेसी बेहतर नीति निर्माण करती है क्योंकि उसे हर स्तर की जानकारी।

निष्कर्ष → किसी भी संगठन के कर्मचारी उसकी क्षमता - अक्षमता निर्धारित करते है। अतः सिविल सेवकों की पर्याप्त ट्रेनिंग, फील्ड पोस्टिंग द्वारा सुधार संभव है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

9. एक कमज़ोर विपक्ष सत्ताधारी सरकार को तो खुश कर सकता है परंतु यह लोकतंत्र के हितों को नहीं साधता है। भारत में हालिया आम चुनावों के परिणाम के आलोक में इस कथन की विवेचना कीजिये। (150 शब्द) 10

A weak opposition may make the government of the day happy but it does not serve the cause of democracy. Discuss the statement in light of the outcome of recent general elections in India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

लोकतंत्र में सत्ता पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका विपक्ष निभाता है क्योंकि वह सरकार को उत्तरदायी बनाता है।

विपक्ष की भूमिका

→ सरकार से प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछकर उत्तरदायित्व बढ़ाना।

→ सरकारी नीतियों की कमियों (लूप होल्स) को उजागर कर, जनता तक पहुंचाना।

→ कानूनों पर पर्याप्त बहस के द्वारा गुणवत्ता को बढ़ाना तथा निहित मुद्दों का समाधान करना।

→ सरकार को निम्नवर्ग, पिछड़ेवर्ग आदि के विकास के संबंध में नीति निर्माण को बाध्य करना।

→ अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार की ~~[illegible]~~ जवाबदेहिता बढ़ाना।

→ कटौती प्रस्ताव द्वारा गलत नीतियों को दूर करना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

→ लोक लेखा समिति, ~~प्राक्कलन समिति~~, CAG आदि की रिपोर्ट पर चर्चा द्वारा मितव्ययिता बढ़ाना।

• कमजोर विपक्ष सरकार को जवाबदेहिता एवं उत्तरदायित्व से दूर करता है। हाल ही हुये चुनावों में विपक्ष, निर्धारित 10% सीटें प्राप्त करने में असफल रहा।

आगे की राह:-

→ विपक्ष द्वारा शैडो कैबिनेट का गठन कर सरकार पर अधिक सक्षम नियंत्रण बनाया जा सकता है।

→ विपक्ष द्वारा मीडिया व NGO के समर्थन से जनता की राय को संसद के पटल तक पहुँचाना ताकि वास्तविक लोकतंत्र सफल हो सके।

सारांशत: कहा जा सकता है कि विपक्ष की भूमिका ही लोकतंत्र की मजबूती का आधार है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

10. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.) के निर्धारण हेतु अनुपालित मानदंडों का उल्लेख कीजिये। उनके द्वारा किन मुद्दों का सामना किया जाता है? साथ ही इन मुद्दों के समाधान के लिये सरकार द्वारा किये गए उपायों का भी उल्लेख कीजिये। (150 शब्द) 10

State the criteria followed for the determination of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs). What are the issues faced by them? Also mention the measures taken by the government to address these issues. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारतीय जनजातियों में कुछ जनजातियों को PVTG का दर्जा दिया गया है अर्थात् सरकार द्वारा उनके संरक्षण का विशेष प्रावधान किया जाएगा।

PVTG के मानदंड

→ गिरती हुई या स्थिर जनसंख्या।
→ आदिम कृषि प्रणाली की निरन्तरता।
→ शिक्षा का बेहद कम स्तर।
→ बच्चों में कुपोषण की स्थिति गंभीर होना।
→ मुख्य धारा से अलगाव।

भारत में 75 जनजातियों को PVTG का दर्जा दिया गया है, जिनमे पूर्वोत्तर एवं अंडमान निकोबार मे अधिकांश जनजातियाँ है।

उदाहरण - जारवा, सेंटनली, सहरिया आदि।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

इनकी समस्याएं :-

→ आदिम कृषि प्रणाली, जीवन निर्वहन ~~आय के~~ के लिए अपर्याप्त।

→ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव होने के कारण कुपोषण, बालमृत्युदर, मातृमृत्युदर की स्थिति गंभीर।

→ मुख्य धारा से दूरी, इन्हें शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास से दूर रखती है, जिससे गरीबी दुश्चक्र की स्थिति के शिकार हैं।

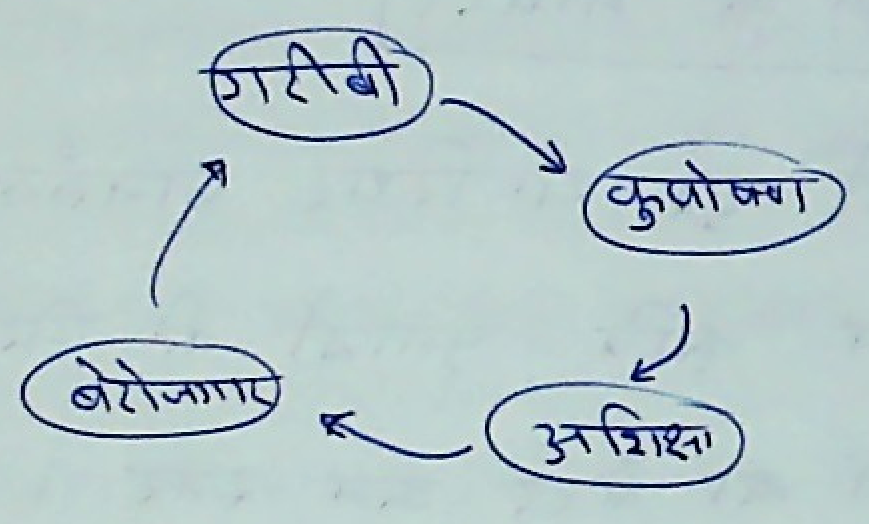

सरकारी उपाय

→ सरकार ने लघु वनोपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए वन धन केन्द्रों की स्थापना की है।

→ वनबंधु कल्याण योजना द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल की सुविधा पहुँचाई जा रही।

→ वनाधिकार अधिनियम, 2006 द्वारा जल, जंगल, जमीन पर अधिकार दिये गये हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

11. राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप, 2019 भारत के शिक्षा क्षेत्र को एक नया आकार दे सकता है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

Draft National Education Policy, 2019 can give a new shape to India's education sector. Critically examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप पेश किया गया, जो तीन दशक पुरानी शिक्षा नीति का स्थान लेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप की विशेषताएं

→ इसके अन्तर्गत प्री-स्कूलिंग को ध्यान में रखा गया है।

→ शिक्षा पर GDP के 6% खर्च करने का प्रावधान है।

→ शिक्षा में वैज्ञानिक चेतना का विकास बचपन से ही किये जाने का प्रावधान है।

→ यह शिक्षा नीति सभी हितधारकों को जवाबदेह बनाती है।

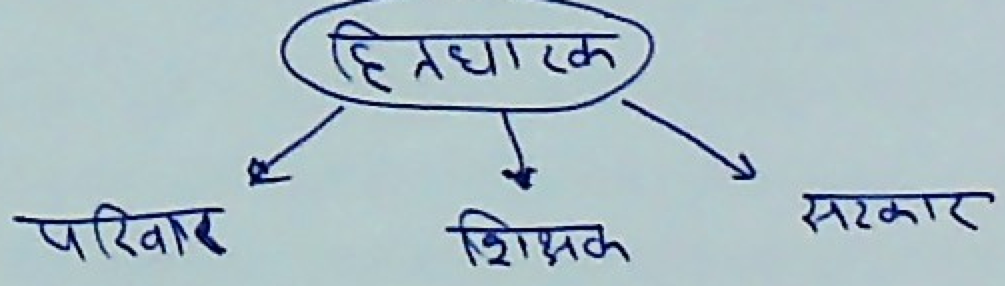

→ नामांकन के लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात् अब

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

रिटेंशन रेट बढ़ाने तथा गुणवत्ता में सुधार पर बल दिया गया है। उम्र के साथ बढ़ते ड्राप आउट को कम करने पर ध्यान

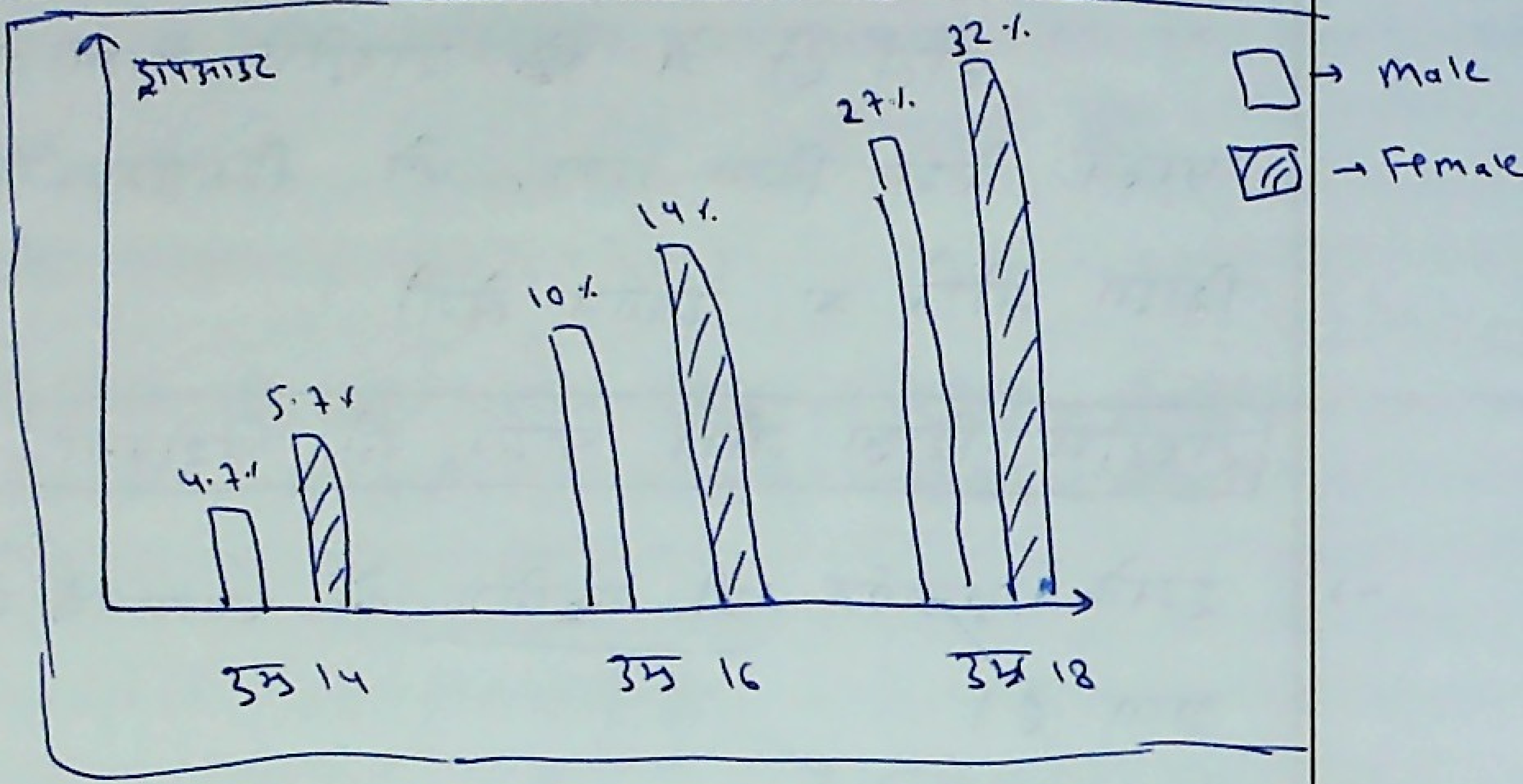

→ शिक्षा के समावेशन, पहुँच तथा गुणवत्ता पर बल दिया गया है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

12. "सामाजिक अंकेक्षण परिकल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को कम करने में सहायता प्रदान करता है।" इस कथन का परीक्षण कीजिये और भारत में सामाजिक अंकेक्षण को प्रणालीबद्ध करने में आने वाली बाधाओं पर भी चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

"Social audit helps to narrow gaps between vision and reality." Examine the statement and also discuss the impediments in institutionalization of social audit in India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सामाजिक अंकेक्षण से तात्पर्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी द्वारा गुणवत्ता को बढ़ाना है।

सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया :

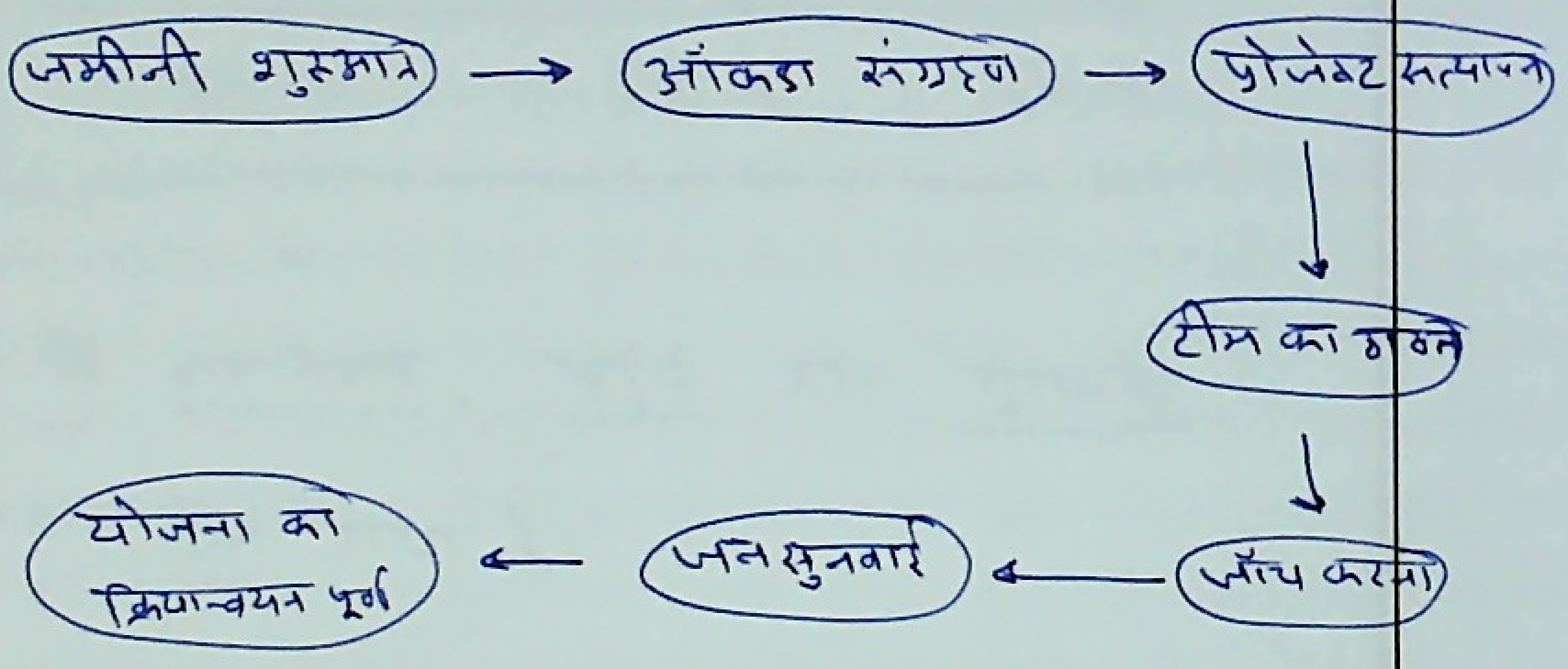

सामाजिक अंकेक्षण के लाभ

→ सामाजिक अंकेक्षण द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में उपस्थित लीकेज की समस्या दूर होती है।

→ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तथा गुणवत्ता में सुधार होता है।

→ यह Bottom-UP एप्रोच से संचालित होता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

→ जनता की भागीदारी, जनता के लिए आवश्यक योजनाओं के निर्माण पर बल देती है।

→ जनता की भागीदारी पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता को बढ़ाती है, जो नागरिक सशक्तीकरण में भूमिका निभाती है।

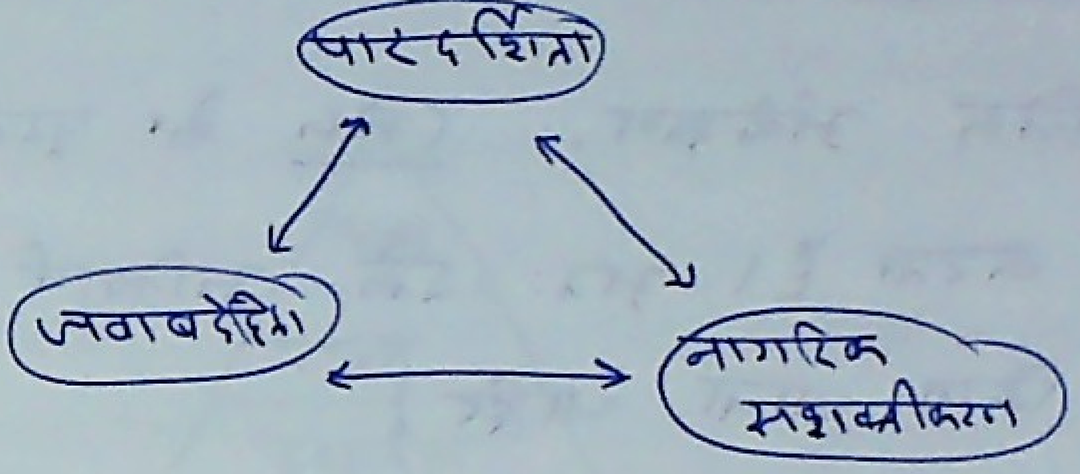

इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकार द्वारा परिकल्पित योजना, अपने वास्तविक रूप में धरातल पर आती है, जिससे सरकार तथा जनता दोनों का फायदा होता है।

हाल ही में मेघालय द्वारा एक अधिनियम बनाकर सभी सरकारी योजनाओं के लिए सोशल ऑडिटिंग अनिवार्य कर दिया।

बाधाएँ

→ जनता की जागरूकता का अभाव इसमें सबसे बड़ी बाधा है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

→ डाटा तक अपर्याप्त पहुँच, इसके अप्रभावी होने की आशंका बढ़ा देता है।

→ मीडिया द्वारा इसकी उपेक्षा करनी।

→ जनता एवं प्रशासन में सूचना अन्तराल।

आगे की राह

→ सामाजिक अंकेक्षण, CAG के पूरक की तरह कार्य करता है। अतः इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए।

→ मनरेगा जैसी योजनाओं में इसकी अनिवार्यता ने दक्षता में वृद्धि की है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सामाजिक अंकेक्षण ~~एक~~ भ्रष्टाचार कम करने का सशक्त साधन बन सकता है, बशर्ते इसके समक्ष आने वाली बाधाओं को दूर किया जाये।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

13. 73वाँ संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के समक्ष आने वाली प्रणालीगत चुनौतियों को हल करने में नाकाम रहा है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

73rd Amendment Act has failed to address the systemic challenges faced by Panchayati Raj Institutions (PRIs). Critically analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

73 वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्र में शासन के तीसरे स्तर का गठन किया गया और शासन को अधिक प्रभावी बनाया गया।

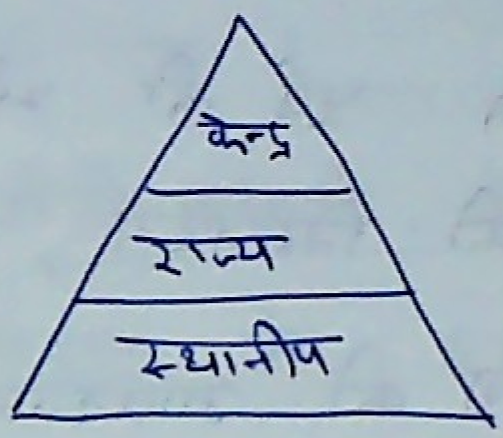

पंचायती राज संस्थाओं के लाभ

→ आधारभूत एवं सहभागी लोकतंत्र।

→ पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व।

→ महिला सशक्तीकरण में भूमिका।

पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष चुनौतियाँ

→ पर्याप्त वित्तीय स्रोत का अभाव होना। यह 73 वें संविधान संशोधन द्वारा भी दूर नहीं हो सका।

→ पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित हुई किन्तु निर्णयन में

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भूमिका नहीं है। प्रधान पति, सरपंचपति की अवधारणा।

→ SC/ST को प्रशासन में भागीदारी के लिए एक मंच की भांति है किन्तु जातिगत व्यवस्था ने इनके प्रभावी होने का विरोध किया है। उच्च जातियों द्वारा वोटिंग नहीं की जाती।

→ नीति-निर्माण में पूर्व की भांति ही TOP-Down एप्रोच की निरन्तरता, जबकि Bottom UP नीति निर्धारण की आवश्यकता।

→ प्रतिनिधियों में पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी।

किन्तु ऐसा नहीं है कि ये संस्थाएं पूर्णतः विफल रही है। महिला की भूमिका बढ़ी है साथ ही अब निर्णयन प्रक्रिया में भी लगातार बदलाव आ रहा है।

युवा वर्ग लगातार इस ओर आकर्षित हुआ है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सरकार द्वारा पर्याप्त महत्त्व दिया गया है। इसके लिए राज्य वित्त आयोग द्वारा फंड दिया जा रहा है।

नीति निर्माण में इनकी भूमिका बढ़ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना आदि में लाभार्थी चयन ग्राम सभा द्वारा ही किया गया।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ तथा स्वच्छ भारत मिशन में PRI की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है।

आगे की राह

→ पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तीकरण ही गांधी के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने के सिद्धांत को सफल कर सकता है।

- राज्य सरकारों द्वारा इन्हें पूर्ण शक्तियों का हस्तान्तरण कर सशक्त किया जाना आवश्यक है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

14. किसी लोकतंत्र में एक स्वतंत्र और जवाबदेह न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों का सर्वोत्तम संरक्षोपाय है। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

An independent and accountable judiciary is the best safeguard of citizens' rights in a democracy. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लि... चाहिये। (Candidate must... write on this ma...)

किसी भी लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका ही सरकार के तीनो अंगों में समन्वय स्थापित करती है।

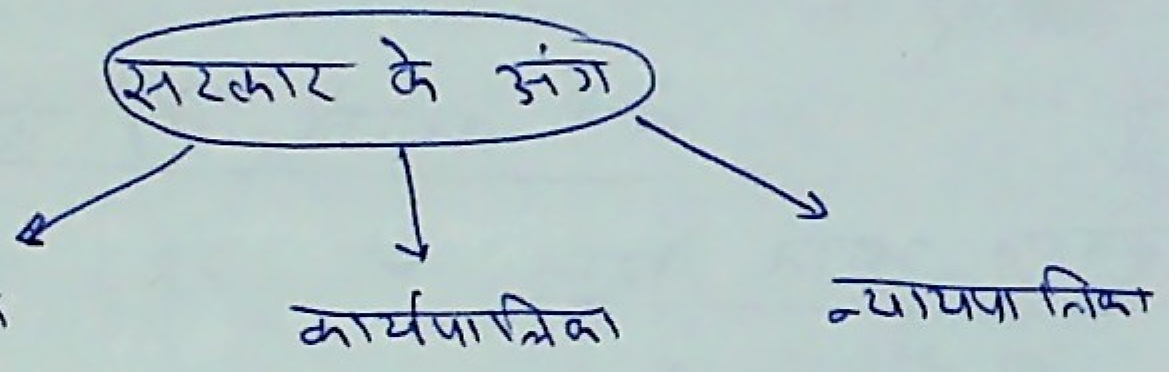

स्वतंत्र एवं जवाबदेह न्यायपालिका के लाभ

→ ~~संस्क~~ संसद द्वारा बनाये गये कानूनो की जाँच करना।

→ ~~मानवाधिकारों~~ मूल अधिकारो के उल्लंघन की स्थिति में असंवैधानिक घोषित करना।

→ सरकारी अक्षमता को दूर करते हुये जनहित याचिकाओं के माध्यम से निर्देश देना।

→ मूल अधिकारो की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की रिट जारी करना। जैसे - बंदी प्रत्यक्षीकरण

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

→ समय के साथ मूल अधिकारों की पुनर्व्याख्या करना। जैसे- शुद्ध हवा की प्राप्ति को जीवन के अधिकार में शामिल करना।

स्वतंत्र न्यायपालिका सरकार को बेहतर नीति निर्माण के लिए प्रेरित करती है क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन एवं न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका के दो महत्वपूर्ण हथियार है।

न्यायपालिका द्वारा समय-समय पर अपने निर्णयों के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता में सुधार को बढ़ावा दिया है, जिससे जनता एवं प्रशासन की दूरी कम हुई है तथा सूचना-अन्तराल कम होने के कारण जनता के अधिकारों की रक्षा हुई है।

न्यायपालिका द्वारा निर्वाचन प्रणाली में सुधार हेतु दिये गये दिशा निर्देश मताधिकार के संरक्षण में भी भूमिका निभाते है क्योंकि इससे अपराधीकरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लि चाहिये।
(Candidate must write on this ma

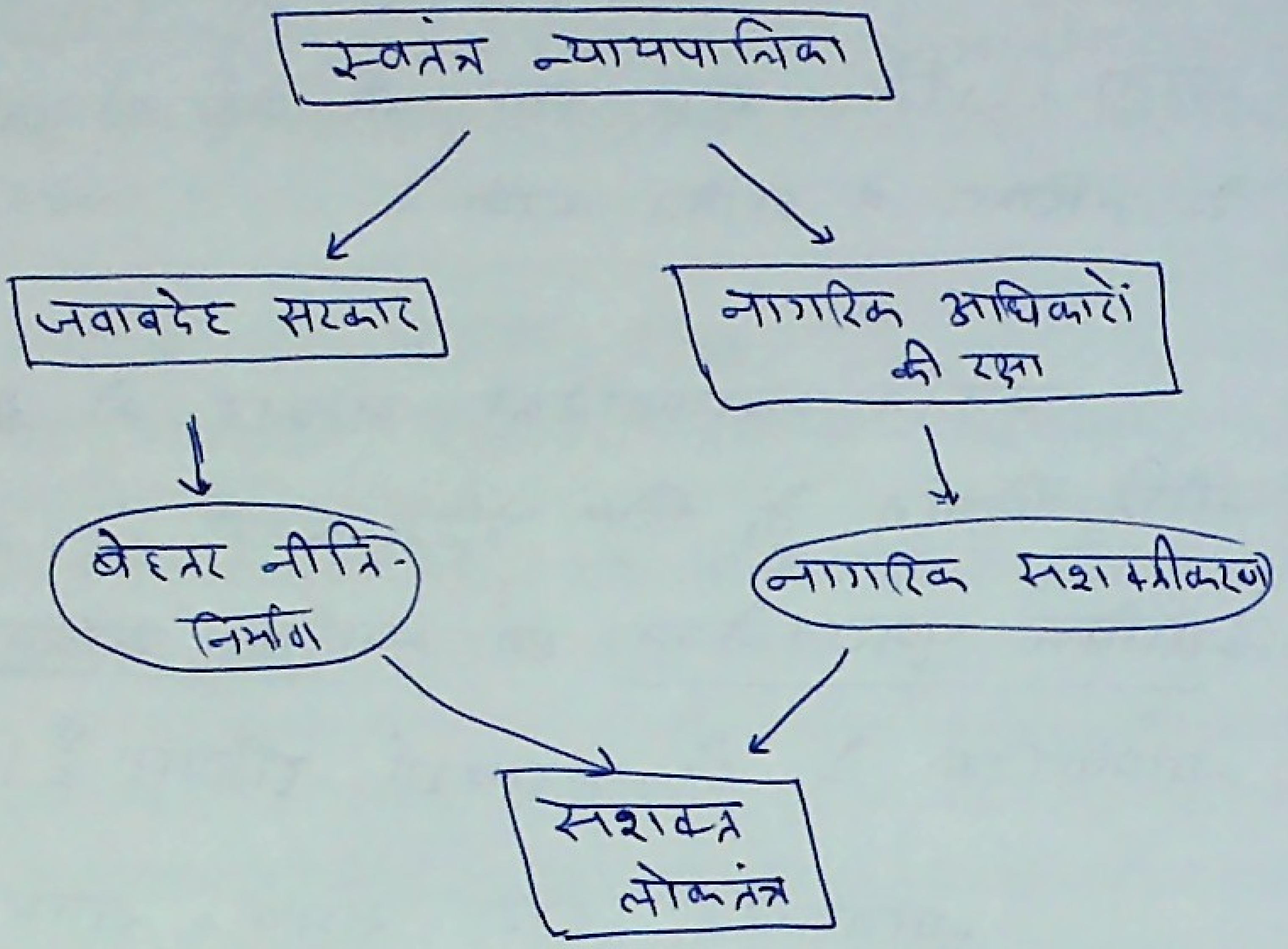

सारांशत: कहा जा सकता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र को मजबूत बनाती है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

15. स्वयं सहायता समूह गरीबों को सूक्ष्म वित्त सेवाओं के वितरण के लिये सबसे प्रभावी तंत्र के रूप में उभरे हैं। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

Self-Help Groups have emerged as the most effective mechanism for delivery of microfinance services to the poor. Critically examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

स्वयं सहायता समूहों से तात्पर्य एक-समान आर्थिक स्थिति वाले लोगों द्वारा आपसी बचत के द्वारा समूह निर्माण करना है। वर्तमान में भारत में ~~कमक~~ उपस्थित SHG का 90% महिलाओं द्वारा संचालित है।

SHG की भूमिका

→ SHG के माध्यम से लोगों में बचत की प्रवृत्ति का विकास होता है, जो उद्यमिता के लिए आवश्यक पूंजी का स्रोत है।

→ SHG के द्वारा निर्धारित पूंजी जमा कर बैंकों से ऋण की प्राप्ति की जा सकती है। इसके लिए SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके दो मॉडल है -

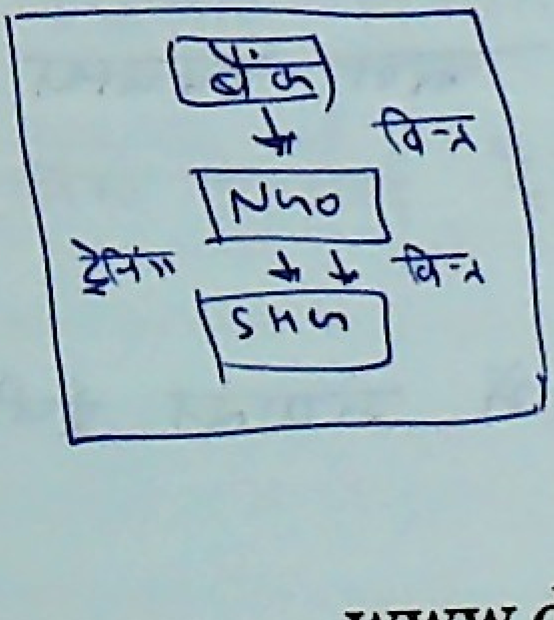

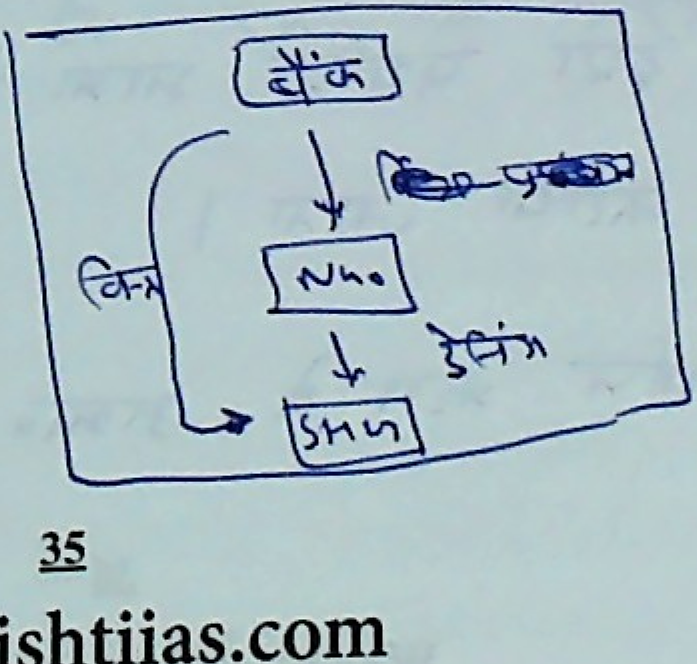

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

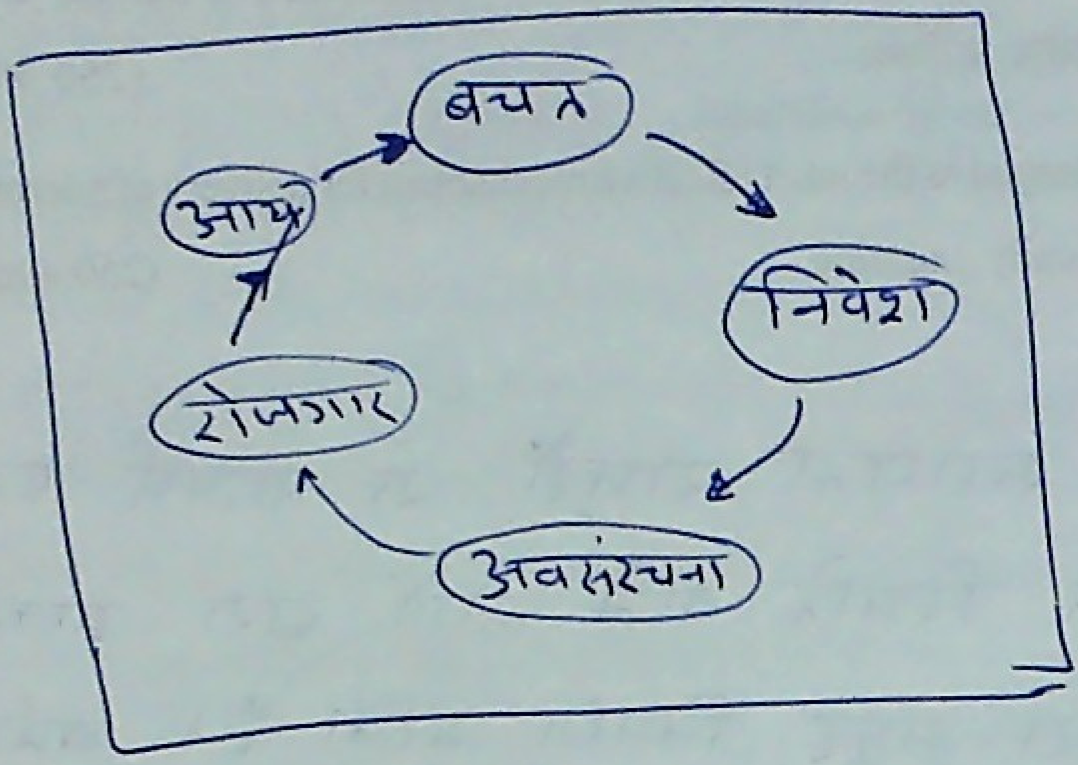

→ SHG के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के वैकल्पिक स्रोतों का विकास हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को बल मिला है।

→ महिलाओं में आर्थिक निर्भरता स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर निवेश बढ़ाती है, जो गरीबी दुश्चक्र पर प्रहार कर, मानव संसाधन विकास द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करता है।

चुनौतियां

→ बैंको द्वारा पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता।

→ पर्याप्त ऋण के अभाव में संचालन पूंजी

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

में कमी से उद्यम के ठप होने तथा सदस्यों के ऋण ग्रस्त होने का खतरा।

→ प्रभावी सदस्यों द्वारा बचत की पूँजी का दुरुपयोग करना।

→ प्रबंधन कौशल के अभाव में उचित निवेश नहीं कर पाना।

आगे की राह

→ हाल ही में नाबार्ड द्वारा ई-शक्ति कार्यक्रम द्वारा SHG के डिजिटलीकरण पर बल दिया।

→ सरकार द्वारा SHG को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना प्रारंभ की गई।

~~निष्कर्षत~~. कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पूँजी निर्माण, मानव संसाधन विकास एवं उद्यमिता विकास में SHG ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

16. भारत जैसे देश में आर्थिक प्रगति और राजनीतिक स्थिरता के लिये संतुलित क्षेत्रीय विकास अति आवश्यक है। 'आकांक्षी ज़िलों के परिवर्तन' कार्यक्रम के आलोक में इस कथन की विवेचना कीजिये। (250 शब्द) 15

Balanced regional development is quite essential for economic progress and political stability in a country like India. Discuss the statement in light of 'Transformation of Aspirational Districts' programme. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लि चाहिये। (Candidate must write on this ma

नीति आयोग ने समावेशी विकास की अवधारणा पर बल देते हुये 115 पिछड़े जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम के घटक

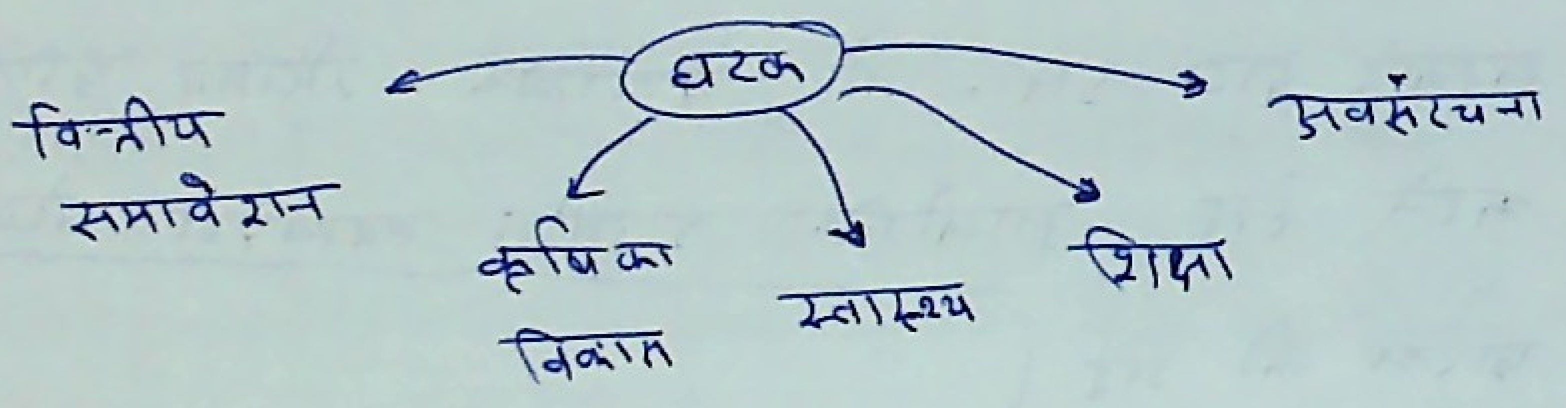

संतुलित क्षेत्रीय विकास में इसकी भूमिका

→ आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) के द्वारा पिछड़े जिलों में सभी क्षेत्रों पर समान बल दिया जा रहा है ताकि आगामी 3 वर्ष में राज्य के सर्वश्रेष्ठ जिले के समकक्ष तथा 5 वर्षों में राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ जिले के समकक्ष

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

लाया जा सके।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे क्षेत्रों का विकास करना इन क्षेत्रों के <u>सामाजिक-आर्थिक विकास</u> को प्रेरित करेगा, जिससे विकास की दौड़ में पिछड़े ~~जनों~~ ये जिले आगे प्रगति करेंगे।

सापेक्षिक वंचना ⇓ $\propto$ विकास ⇑

चूंकि सापेक्षिक वंचना के कारण जनता एवं प्रशासन में सहयोगात्मक संबंध की बजाय दूरी बढ़ती जाती है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में <u>समस्या</u> एवं <u>लीकेज</u> होता है, जो विकास में बाधक है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत <u>रियल टाइम डाटा संग्रहण</u> पर बल दिया जा रहा है, जो प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लि... चाहिये।
(Candidate mus... write on this ma...

चूंकि सापेक्षिक वंचना क्षेत्रवाद की भावना को जन्म देती है, जिससे विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। अतः आवश्यक है कि क्षेत्रीय विकास में समावेशिता का संचार हो।

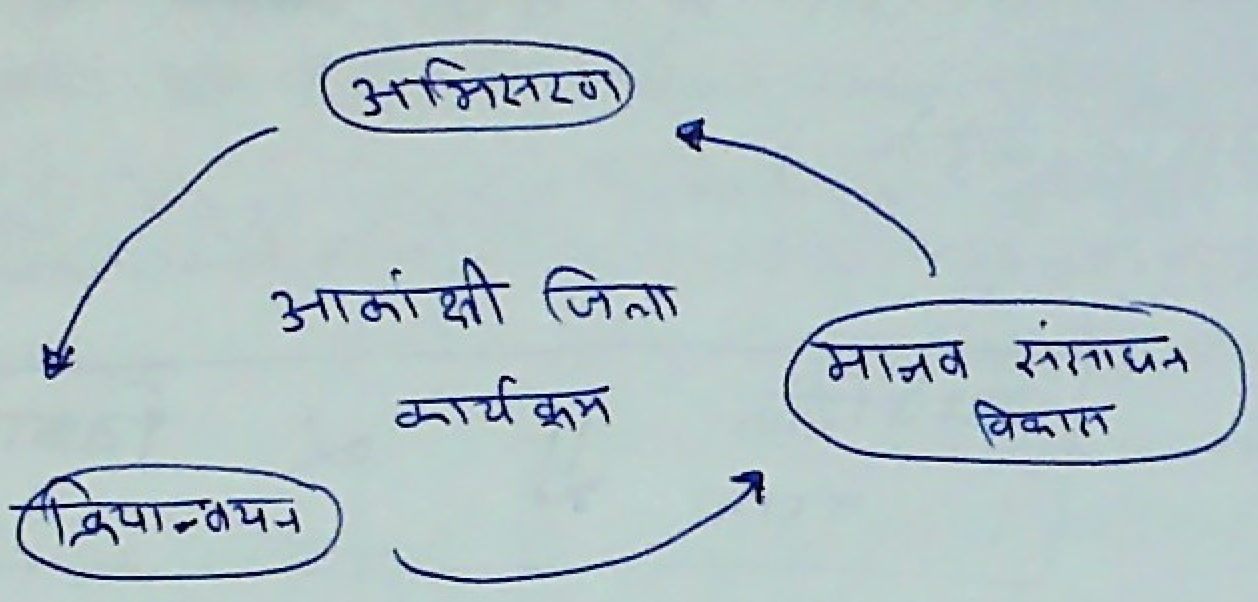

सारांशतः कहा जा सकता है कि यदि भारत को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करते हुये विकास पथ पर बढ़ना है, तो समावेशी क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना होगा।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

17. शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.) भारत की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति को आगे बढ़ाने का एक संभावित मंच है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Shanghai Cooperation Organization (SCO) is a potential platform to advance India's 'Connect Central Asia' policy. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

हाल ही में भारत को 'शंघाई सहयोग संगठन' के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इससे भारत को सेंट्रल एशिया के देशों से वार्ता का एक मंच प्राप्त हुआ।

भारत के लिए निहितार्थ -

→ भारत मध्य एशियाई देशों को अपने ~~एक्सटे~~ 'एक्सटेंडेड पड़ोसी' का दर्जा देता है इसलिए वार्ता के एक मंच के रूप में SCO की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

→ मध्य एशियाई देशों की स्थलबद्धता इन्हें भारत से कनेक्ट करने में एक बाधक

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लि[खना] चाहिये।
(Candidate must [not] write on this mar[gin])

है किन्तु एक मंच के रूप में SCO ने इस बाधा को दूर किया है।

→ इस मंच के माध्यम से भारत द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौतों के द्वारा इन देशों से अपने संबंधों को सुदृढ़ कर सकता है।

→ मध्य एशियाई देशों तक पहुँच के लिए भारत द्वारा INSTC, अश्गाबात समझौता आदि कई प्रयास किये है किन्तु SCO के द्वारा सभी राष्ट्रों से साझा वार्ता संभव है।

→ मध्य एशियाई राष्ट्रों से ऊर्जा के स्रोत के रूप मे यूरेनियम की प्राप्ति संभव है।

चुनौतियां

→ इस संगठन का चीन के पक्ष में झुका होना।

→ चीन द्वारा इन देशों में डेब्ट ट्रैप की नीति द्वारा आर्थिक नियंत्रण।

→ हाल ही मे ईरान पर प्रतिबंध के कारण

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत एवं ईरान संबंधों में गिरावट।

→ संगठन में पाकिस्तान की उपस्थिति।

आगे की राह

→ पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरने एवं मध्य-एशियाई राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अतः भारत को चाबहार बंदरगाह के माध्यम से इन राष्ट्रों तक अपनी पहुँच सुदृढ़ तरीके से सुनिश्चित करनी चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लि
चाहिये।
(Candidate must
write on this mar

18. दक्षिण एशिया में सहयोग को बढ़ाने में सार्क की विफलता ने क्षेत्रीय देशों को बिम्सटेक के रूप में एक व्यावहारिक विकल्प तलाशने हेतु प्रेरित किया है। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

The failure of SAARC to nurture cooperation in South Asia has pushed regional players to explore BIMSTEC as a viable alternative. Examine. (250 words) 15

दक्षिणी एशिया में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने तथा शांति स्थापना के लिए सार्क का गठन किया गया किन्तु सीमा पार आतंकवाद पर पाक के रवैये ने इसके स्थान पर नवीन विकल्प तलाशने को मजबूर किया

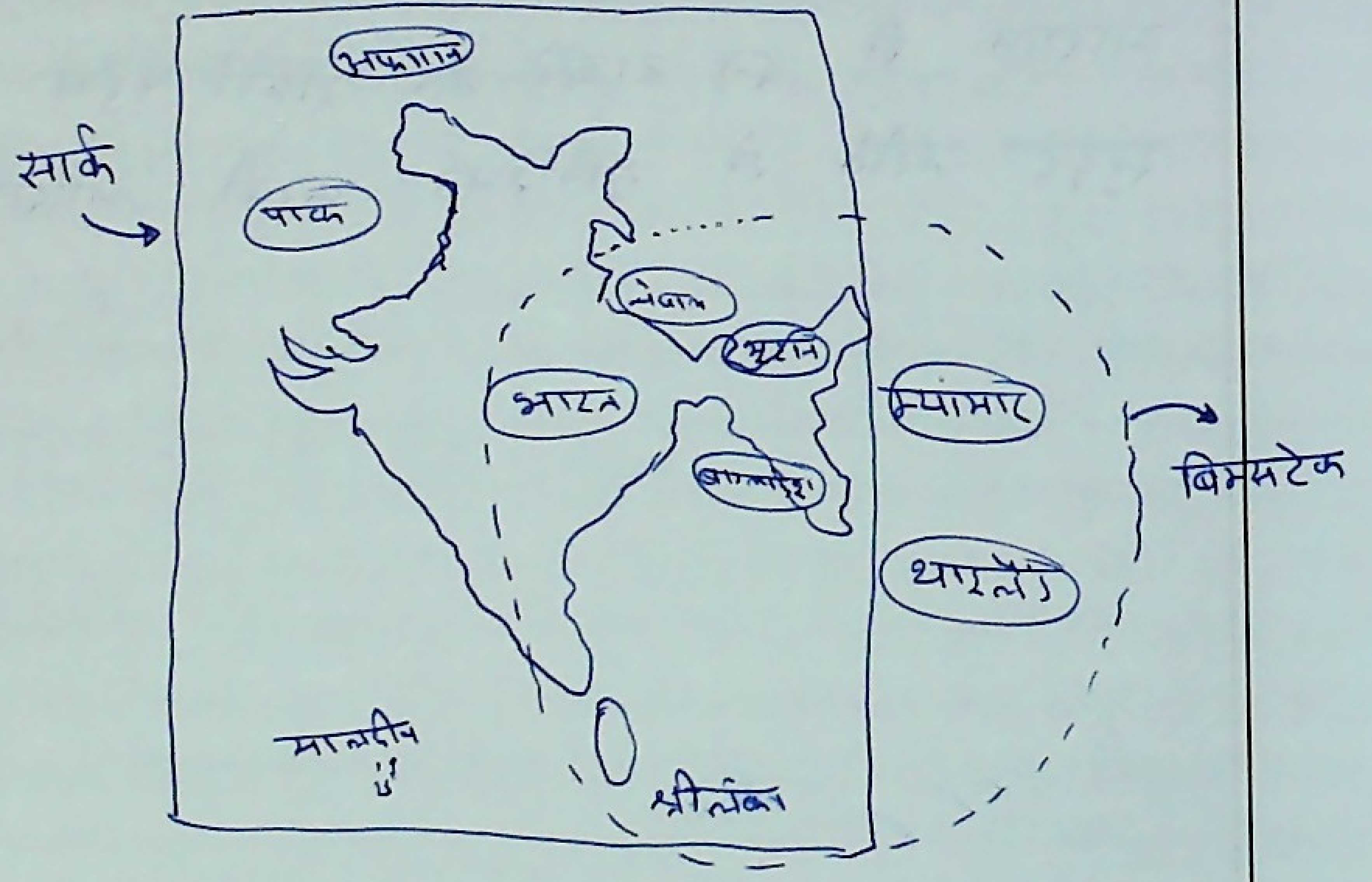

सार्क की विफलता का कारण

→ पाकिस्तान द्वारा लगातार सीमापार आतंकवाद को प्रोत्साहित करना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

→ आर्थिक व्यापार में बाधा उत्पन्न करना।

→ मुद्दों पर नकारात्मक प्रवृत्ति।

विकल्प के रूप में बिम्सटेक

बिम्सटेक में अधिकांश राष्ट्र वो ही है. जो सार्क में है साथ ही पाकिस्तान की अनुपस्थिति इसे आतंकवाद पर एकजुट करती है।

सार्क के विपरीत बिम्सटेक व्यापार, तकनीकी, शिक्षा, सहयोग आदि कई मुद्दो को समाहित करता है।

बिम्सटेक के सभी राष्ट्र समान विकास की प्रेरणा से युक्त है तथा आपसी सहयोग की भावना से युक्त है।

बंगाल की खाड़ी का लगातार बढ़ता महत्व इस संगठन का आधार है। साथ ही चीन की डेब्ट ट्रैप नीति में फँसे इन राष्ट्रो को भारत सहयोग कर सकता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लि... चाहिये।
(Candidate must ... write on this ma...)

'ब्लू इकॉनोमी' के बढ़ते महत्व के संदर्भ में यह संगठन एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए यह संगठन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कनेक्टीविटी की समस्या का समाधान होगा।

भारत की एक्ट ईस्ट नीति की सफलता में भी यह संगठन भूमिका निभा सकता है।

आगे की राह

→ भारत को बिम्सटेक को बढ़ावा देना चाहिए किन्तु सार्क की कीमत पर नहीं क्योंकि क्षेत्रीय विकास तभी संभव है, जब पाकिस्तान का विकास हो। ऐसे में सार्क पर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है क्योंकि पडोसी नहीं बदले जा सकते।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

19. भारत के लिये क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आर.सी.ई.पी.) का क्या महत्त्व है? विशेष रूप से चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये इसके निहितार्थ का परीक्षण कीजिये।

(250 शब्द) 15

What is the significance of Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) for India? Examine its implications for the Indian economy especially in the context of free trade agreement with China.

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के संगठन के साथ कुछ बाहरी राष्ट्रों का संगठन क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी का रूप है।

RCEP = आसियान + 6 → चीन, भारत, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया

भारत के लिए महत्त्व

→ इससे भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति को प्रभावी रूप में लागू कर सकता है, जिससे पूर्वोत्तर का विकास संभव है।

→ मुक्त व्यापार समझौते के कारण भारत के निर्यात में वृद्धि संभव है। (मेक इन इंडिया)

→ क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलने से दक्षिणी एशिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का समग्र विकास संभव है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

→ इन राष्ट्रों में भारत तकनीकी निर्यात तथा अंतरिक्ष क्षेत्र मे सहयोग का लाभ कमा सकता है।

चीन के साथ मुक्त व्यापार

चीन द्वारा वर्तमान मे किये जा रहे अधिकांश निर्यात पर भारत सरकार द्वारा अधिक मात्रा में सीमाशुल्क के साथ डंपिंग शुल्क तथा काउंटरवेलिंग शुल्क लगाया जाता है। ऐसे मे मुक्त व्यापार के द्वारा भारत में चीनी वस्तुओं की सहज उपलब्धता स्थानीय कंपनियों पर बुरा प्रभाव डालेगी।

साथ ही प्राप्त सीमाशुल्क में कमी सामाजिक- आर्थिक निवेश पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगी।

किन्तु इससे भारत को भी लाभ संभव है क्योंकि सेवाओं के संबंध में मुक्त व्यापार लागू होने से भारत अपनी सस्ती

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

सेवाएँ वहाँ उपलब्ध करा सकता है।

इसके अतिरिक्त जेनेरिक मेडिसीन जैसे क्षेत्रों में भारत अपनी बढ़त का लाभ ले सकता है।

निष्कर्ष -

RCEP में शामिल होने से भारत को लाभ एवं हानि दोनों का सामना उठाना पड़ेगा। अत: आवश्यकता है कि पर्याप्त शिक्षा एवं कौशल विकास द्वारा मेक इन इंडिया को सफल बनाया जाये ताकि RCEP का लाभ लिया जा सके।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

20. निरंतर हठधर्मिता दिखाते चीन के साथ संबंधों को बनाए रखना भारतीय विदेश नीति की प्रमुख चुनौतियों में से एक के रूप में उभरा है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में चर्चा कीजिये।

(250 शब्द) 15

Dealing with an increasingly assertive China has emerged as one of the principal challenges of Indian foreign policy. Discuss in the context of China's growing influence in South Asian region.

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

भारत एवं चीन दो एशियाई राष्ट्र परस्पर शक्ति संतुलन के कारण लगातार तनाव की स्थिति में रहते है। ऐसे में भारत द्वारा चीन के साथ संबंध बनाने में चुनौतियों का ~~सम~~ सामना करना पड़ता है।

भारत - चीन के मुख्य मुद्दे

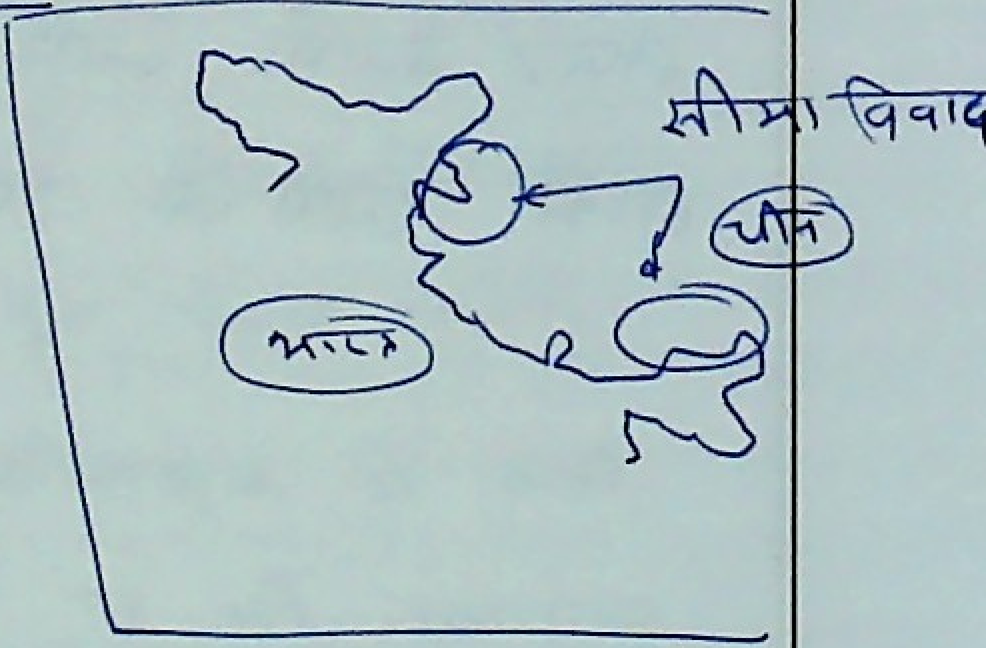

→ सीमा विवाद

→ BRI का भारतीय सम्प्रभुता पर खतरा।

→ नदी जल समझौते

→ विभिन्न मंचों पर चीन द्वारा भारत का विरोध।

→ चीन की डेब्ट ट्रैप नीति

→ हिन्द महासागर में बढ़ता प्रभाव।

→ भारत को घेरने की नीति (स्ट्रींग ऑफ पर्ल्स)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

इन सब मुद्दों के कारण चीन से संबंध निर्धारण में अनेक चुनौतियाँ सामने आती है।

दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव

→ चीन लगातार अपने सस्ते उत्पादों का निर्यात इन देशों में कर रहा है। (BRI)

→ आर्थिक सहायता के नाम पर डेब्ट ट्रैप में फंसना।

→ विभिन्न बंदरगाहों द्वारा भारत को घेरना।

→ अंतरिक्ष कार्यक्रम के द्वारा लगातार भारत ~~को~~ के साथ प्रतिस्पर्धा।

→ BRI के माध्यम से व्यापार

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

आगे की राह

→ भारत को अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

→ पड़ोसी राष्ट्रों को बिना शर्त सहायता राशि प्रदान की जानी चाहिए।

→ अंतरिक्ष में अपनी पहुँच का लाभ प्रदान करना चाहिए। जैसे- सार्क सैटेलाइट

→ व्यापार के लिए चीन के ~~प्र~~ प्रतिद्वंद्वी के रूप में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का विकास किया जाना चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation